Hindustan (Date: 29/07/2019)

परिवहन विभाग पॉलिसी बनाएगा, पहले विस अध्यक्ष, विप कार्यकारी सभापति और उपमुख्यमंत्री को मिलेगी कार

मंत्री और अफसर अब करेंगे इलेक्ट्रिक कार की सवारी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के सभी मंत्री और अफसर इलेक्ट्रिक कार की सवारी करेंगे। परिवहन विभाग ने अभी दो इलेक्ट्रिक कारें खरीदी हैं। इसमें एक कार मुख्यमंत्री को मिला है। अब वह सरकार के सभी मंत्रियों व अफसरों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा। परिवहन विभाग इसके लिए पॉलिसी बनाएगा। इसके पूर्व परिवहन मंत्री व अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक होगी। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लेने के बाद ही परिवहन विभाग पॉलिसी बनाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कारें राज्यपाल, विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति, उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री को मिलेंगी। इसके बाद अन्य मंत्रियों को कारें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद सभी विभागों के प्रधान सचिव व आला पुलिस अधिकारियों के लिए कारों की खरीदारी होगी। फिर जिले के सभी डीएम व एसपी को मुहैया कराया जाएगा। विभाग कार खरीदने के लिए वित्त विभाग से फंड मांगेगा। परिवहन विभाग, ऊर्जा मंत्रालय की कंपनी एनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (इइएसएल) से इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा। जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक कार की खरीद अन्य विभागों में भी की जाएगी। परिवहन विभाग की योजना है कि सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक कार का परिचालन सुनिश्चित कर दिया जाए।

01 इलेक्ट्रिक कार की कीमत 11 लाख रुपए है, वित्त विभाग से राशि लेकर खरीदी जाएंगी कारें

20 चार्जिंग सेन्टर खोले जाएंगे

इलेक्ट्रिक कार को कार चार्ज करने के लिए राजधानी में सभी मंत्रियों व अफसरों के कार्यालय व निजी आवास के आसपास चार्जिंग सेन्टर भी बनाया जाएगा ताकि कार को चार्ज करने में मंत्रियों व अफसरों को कोई कठिनाई न हो। शुरुआती दौर में राजधानी में 20 चार्जिंग सेन्टर खोले जाएंगे।

एक बार चार्ज पर 142 किमी यात्रा

एक बार चार्ज कराने के बाद 142 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंट से चार्ज करने पर मात्र 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, जबकि अल्टरनेटिव करेंट से चार्ज करने पर अधिकतम समय 4-5 घंटे का समय लगेगा। इसकी रफ्तार अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है।